स्कीम	व्यय		
	1991-92	1992-93	1994-95 (अनंतिम)
3. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)	—	—	179.75
$4. नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई)	102.80	70.80	74.77
*5. शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार स्कीम (एस ई ई यू वाई)	50.00	40.00	40.00
*6. प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आई वाई)	—	—	30.00

$ जारी धनराशि

* जारी सब्सिडी राशि

उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए विकास योजनाएं

3604. **श्री अनन्त देवशंकर दवे:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने अपने राज्यों के विकासार्थ कतिपय योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकारों के अपने राज्यों के विकास के लिए प्रस्ताव वार्षिक योजना प्रस्ताव 1994-95 प्रारूप के रूप में भेजे थे जिन्हें योजना आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विधिवत अनुमोदित किया गया था। 1994-95 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के लिए क्रमशः 4561.75 करोड़ रुपये और 2240 करोड़ रुपये अनुमोदित किये गये थे।

Amount Spent on Advertisements

3605. SHRI MOHAMMED AFZAL ALIAS MEEM AFZAL: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state the details of the total amount spent by his Ministry on advertisements given to the Newspapers direct or through DAVP etc. during the period 1992-93 and 1993-94, language-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION. (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): The information is being collected and will be laid on the Table of the House shortly.

उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में मुख्य परियोजना

3606. **श्री आस मोहम्मद:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में कोई मुख्य परियोजना शुरू करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कुल कितनी धन-राशि आबंटित की गई/दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) केन्द्र

सरकार का उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाकों में वार्षिक योजना 1994-95 के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त किसी नई प्रमुख परियोजना को आरंभ करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Study by Planning Commission on Growth of Railway Traffic Freight and Passengers

3607. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission is not carrying out any study about the growth of railways traffic, freight as well as passengers;

(b) if so, how does the Planning Commission make accurate forcecasts:

(c) the steps taken to carry out such studies; and

(d) if rot the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) Consistent with the overall economic growth projection for the Eighth Five Year Plan, the Planning Commission worked out the target for Railway traffic for the terminal year of the plan. This was on the basis of a study of the observed past trends, inter-sectoral relationships as reflected in the Input-Output model and rail transport coefficients for different commodities carried by Railways. The annual targets of Railway traffic are fixed by the Ministry of Railways taking into account the Eighth Plan target and in consultation with Planning Commission and other concerned Ministries.

(d) Does not arise.

Role of Planning Commission in Free-Market Economy

3608. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

. (a) what will be the role of the Planning Commission in the free-market economy in the post liberalisation era;

(b) whether any exercise has been done in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) to (c) The Eighth Five Year Plan document prepared by the Planning Commission stipulates the role of Planning in the context of the new economic scenario. Planning is needed for creating social infrastructure and for human development. Planning is necessary to take care of the poor and the down-trodden. The planning process has to manage the flow of resources across regions for accelerated removal of regional disparities. Planning and more particularly, public sector investment have a major role to play in strengthening the physical infrastructure. Eighth Plan document further specifies that the public sector plan will have to become very selective in the coverage of activities and in making investments.

देश में ऊर्जा की आवश्यकता के संबंध में सर्वेक्षण

3609. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोलाः क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सम्पूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ऊर्जा की आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को ऊर्जा की कितनी मात्रा की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार किन योजनाओं पर विचार